Manufacture of Mica Paper

1597. SHRI AMAR NATH CHAWLA:

SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH :

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state :

(a) whether the Research and Development Organisation of his Ministry for Electrical Industry has evolved a process to manufacture paper from mica;

(b) whether it has entered into an agreement with a firm in Bangalore for the manufacture of mica paper and if so, the name of Bangalore firm and the terms and conditions of the agreement;

(c) the time by which the mica paper is likely to be manufactured; and

(d) the present import of mica paper and the foreign exchange spent on its import every year?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD) : (a) Yes, Sir.

(b) The Research and Development Organisation for Electrical Industry, Bhopal has entered into a collaboration agreement with M/s. Senapathy Whitely (Private) Ltd., of Bangalore, for imparting to the latter the know-how for manufacture of mica paper. The broad terms of the agreement that Research and Development Organisation for Electrical Industry will receive a lump-sum payment of Rs. 1 lakh, and 2½% of the gross sale proceeds as service charges for a period of 5 years from the commencement of commercial production.

(c) The production of mica paper by the Bangalore firm is likely to commence in 1974-75.

(d) Figures in respect of import of mica paper and foreign exchange spent on its import are not readily available as this item is not separately classified in the "Revised Indian Trade Classification" on the basis of which foreign trade statistics are complied.

Manufacture of Steam Car by Delhi Automobile Firm

1598. SHRI NIHAR LASKAR : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether an attempt to produce a steam car in India is being launched by Delhi automobile firm; and

(b) if so, the salient features thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD) : (a) Government have no information in this regard.

(b) Does not arise.

"Phony business of Bombay Telephones"

1600. SHRI B. S. BHAURA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to the news appearing in the *Blitz* dated 10th June, 1972 with the heading "Phony Business of Bombay Telephones";

(b) whether that matter had been investigated; and

(c) if so, the findings of the investigation and the steps taken?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) The allegations contained in the newspaper report were not substantiated.

12.11 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—*Contd.*

REPORTED INCIDENT OF BURNING ALIVE OF TEN HARIJANS IN MACHHARIYA VILLAGE OF MORADABAD DISTRICT IN U.P.

MR. SPEAKER : Shri Ram Niwas Mirdha will now make a further statement regarding the reported recent incident of burning alive of ten Harijan

women and children in Machhariya village of Moradabad District in UP.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : Sir, according to the information received from the State Government an accidental fire broke out in village Machhariya of Moradabad district on 11th May, 1972. The village is inhabited mostly by Harijans. One boy and three girls died on the spot due to the fire. An elderly woman was admitted to the Civil Hospital, Moradabad where she later succumbed to the injuries. Immediate gratuitous relief was provided to the victims of the fire. The State Government propose to provide assistance to the fire victims for the construction of their houses also.

श्री हरी सिंह (खुर्जा) : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अभी यहां पर जो बयान दिया है...

श्री बी० पी० मौर्य (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, इस पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है... ध्यानाकर्षण के संबंध में ही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री हरी सिंह : मैं पूछना चाहता हूं क्या उस गांव के हरिजनों ने जिलाधीश को यह शिकायत की थी कि गांव के लोग जो हरिजन नहीं है वे उनको सता रहे है, उनके खिलाफ जुल्म और अत्याचार कर रहे है ?

साथ ही साथ में यह भी जानना चाहता हूं कि कितने हरिजनों के घर जले इस आग से और उनको किस प्रकार की आर्थिक सहायता दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : मौर्य जी, कालिंग अटेन्शन के दौरान प्वाईन्ट आफ आर्डर नहीं होता।

श्री बी० पी० मौर्य : उस दिन लिस्ट पर मेरा नाम था लेकिन आज गायब है। फिर आप प्रश्न नहीं पूछने देंगे।

अध्यक्ष महोदय : पहले मिनिस्टर का जवाब हो जाये।

श्री राम निवास मिर्धा : राज्य सरकार ने जो सूचना भेजी है उसके मुताबिक उन्होंने इसे एक्सीडेन्टल फायर बताया है और उनके पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है कि कोई विशेष व्यक्तियों ने आग लगाई हो। हरिजनों को सताने के लिए या और किसी मकसद से आग लगाई है, ऐसी सूचना राज्य सरकार की तरफ से हमें नहीं मिली है।

कितने घरों को नुकसान हुआ, उसके बारे में राज्य सरकार ने हमें सूचना दी है कि 108 घरों को नुकसान पहुचा और 38,570 रुपए का नुकसान हुआ।

श्री हरी सिंह : उनको किस प्रकार की सहायता दी गई है या सरकार ने कितनी सहायता देने का प्रस्ताव किया है, इसका जवाब नहीं पाया है। साथ ही इस तरह की जो आग लगी है उसके रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री राम निवास मिर्धा : 8 हजार रुपया तात्कालिक राहत कार्य के लिए तहसीलदार ने उसी समय बांट दिया और राज्य सरकार ने सूचित किया है कि घर बनाने के लिए और कुछ मदद देने वाले रहै।

श्री सरजू पाण्डे (गाजीपुर) : यह हो सकता है कि इस मामले में एक्सीडेन्टल आग लगी हो लेकिन आम तौर से देश के दूसरे भागों से हरिजनों पर अत्याचार के समाचार रोज आते रहते है। बाराबंकी में हरिजनों का सामाजिक बहिष्कार किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप इसी के बारे में पूछिए।

श्री सरजू पांडे : मैं इसी के बारे में पूछ रहा हूं। मै जानना चाहता हूं क्या हरिजनों की प्रोटेक्शन के लिए सरकार कुछ

खास कानून बनाना चाहती है ताकि भविष्य में इस प्रकार के वाकयात न हों ?

श्री राम निवास मिर्धा : प्रश्न नये कानून बनाने का नहीं है। एक बिल अनटचेबिलिटी आफेन्स ऐक्ट को संशोधन करने के लिए सदन के समक्ष प्रस्तुत है। (व्यवधान)..... प्रश्न यह नहीं है कि नये कानून बनाये जाये, प्रश्न यह है कि आज भी जो कानून है उनको ठीक तरह से कार्यान्वित किया जाये। इस संबंध में समय समय पर हम राज्य सरकारों को लिखते है। जब भी हमारी उनसे मीटिंग होती है, हर स्तर पर यही कहा जाता है कि इस विषय में आप पूर्ण रूप से सचेत रहे और उसकी जांच ठीक ढंक से हो, प्रासीक्युशन तत्परता से हो। जो भी सारा राजकीय प्रशासन है और जिला प्रशासन है वह जो भी कानून बने है हरिजनों की सुरक्षा के लिए उनको कार्यान्वित करे। यह बात समय समय पर हम राज्य सरकारों को लिखते रहे है और उनको आगाह करते रहे है।

श्री हुकम चन्द कछवाय (मुरैना) : अध्यक्ष महोदय, इस गाव मे पिछले अनेकों दिनों से हरिजनों पर नाना प्रकार के अत्याचार होते आये है जिसकी सूचना एव शिकायत वे लोग अपने जिलाधीश को समय समय पर बराबर देते रहे है। वे लोग पुलिस थाने पर भी रिपोर्ट लिखाते रहे है। अब जो आपकी एजेन्सी है वह है राज्य सरकार परंतु राज्य सरकार ने जो सूचना दी है वह सत्य से पर है। राज्य सरकार ने आपको सही जानकारी नहीं दी है। यह जो आग लगी है और इतनी बडी संख्या में मकान जल है यह अनायास ही नही लगी है बल्कि योजनाबद्ध आग लगाई गई है। यदि आप केन्द्र से कोई जांच बिठायेंगे या अपना कोई आदमी वहां पर जांच करने के लिये भेजेंगे तो वास्तव में आपको सही बात का पता लगेगा। मंत्री महोदय ने अपने बयान में कहा है कि हमने उनको कुछ सहायता दी है, मै जानना चाहता हूं इतने परिवार के लोग मरे है उन्हें आपने कितनी सहायता दी है और जिनके मकान जले है उन्हे आपने कितनी सहायता देने की घोषणा की है या राज्य सरकार ने वचन दिया है कि हम दे रहे है या दे दी है? दो बाते है– देने जा रहे है या तत्काल सहायता दे दी है– तो मै जानना चाहता हूं वह एमाउंट कितना है और आपकी ओर से जो सहयोग मिलने वाला है वह कितना है तथा राज्य सरकार से मिलने वाला कितना सहयोग है ?

इसके साथ साथ मैं यह भी जानना चाहता हू कि जो घटना हुई है उसकी जांच के लिए आप केन्द्र से अपना कोई आदमी या समिति भेजने वाले है क्या? इस प्रकार की घटना महाराष्ट्र मे भी हुई है। महाराष्ट्र में एक मिनिस्टर के पुत्र ने इस प्रकार की घटनाएं की है तथा तमाम देश मे इस प्रकार की घटनाएं हो रही है......

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरी बाते मत करिये, इसी पर रहिए।

श्री हुकम चंद कछवाय : हरिजनों के साथ कई स्थानों पर इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। मैं जानना चाहता हू इस प्रकार की घटनाओं के लिए क्या केन्द्र मे आप कोई ऐसी एजेन्सी बनायेगे जोकि ऐसी घटना होते ही तत्काल अपने आदमी भेजकर उसकी छानबीन और जांच करवाये? यह जो घटना हुई है इसके संबंध मे शेडूल्ड कास्टस् तथा शेडूल्ड ट्राइब्ज के जो कमिशनर है उन्होंने भी कोई कार्यवाही नहीं की है और न ही उन्होंने अपना कोई आदमी इस घटना की जांच करने के लिए भेजा। तो क्या आप उन्हे भी हिदायत देंगे कि जहां

[श्री हुकम चन्द कछवाय]

कही इस प्रकार की घटना हो वहां पर तत्काल उसकी छान बीन और जांच की जाये ताकि सही बात का पता लग सके? एसे मामले मे आपको राज्य सरकार के भरोसे पर नही रहना चाहिए ।

श्री राम निवास मिर्धा : यह कहना उचित नही है कि राज्य सरकार ने इस सबध मे कोई बात छिपाई है या केन्द्रीय सरकार को कोई गलत सूचना दी है। जैसा की बताया गया है यह घटना 11 मई, 1972 की है और राज्य सरकार को या जिला प्रशासन को कोई भी इस प्रकार की शिकायत नही मिली है कि इन झोपडियो को जलाने मे किसी व्यक्ति का या वर्ग विशष का हाथ रहा है...

श्री बी० पी० मौर्य : यह गलत बयानी है।

श्री राम निवास मिर्धा : राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह आग एक्सीडेन्टल लगी है । कोई वहज नही है कि हम राज्य सरकार की बात न माने।

जहा तक हमारी जाच का प्रश्न है, सारी व्यवस्था राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र की है इसलिए उन्ही पर हमे विश्वास रखना पडेगा। हम समय समय पर राज्य सरकारों से सपर्क करते है तथा उन्हे सलाह देते रहते है ।

SHRI B. P. MAURYA: On a point of order. The Minister is not supposed to make a wrong statement on the floor of the House. It is wrong to say that the State Government or the District Magistrate did not know about this incident. This is a wrong statement. I challenge it on the floor of the House.

You are misguiding us. It is a wrong statement of fact. You appoint an enquiry committee, and let the Minister find out. I am prepared to resign my seat if what I have said is proved to be wrong.

श्री हुकम चन्द कछवाय : राज्य सरकार की ओर से गलत जानकारी दी गई है। अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा पुछे गये प्रश्न का उत्तर दिलवाया जाय। मेरे आधे भाग का उत्तर भी अभी आना बाकी रहता है। राज्य सरकार के उपर हमे भरोसा नही है, कन्द्रीय सरकार पर हो सकता है लेकिन हमारा विश्वास उन के ऊपर बिलकुल नही है। चूकि वह गलत बयान दे रहे है इसलिए मेरा कहना है कि केन्द्रीय सरकार अपनी किसी इडिपेडेट एजेसी के मार्फत यह जाच करवाये ।

दूसरी बात मैंने पूछी है कि कितनी मदद केन्द्रीय सरकार न दी है और कितनी मदद राज्य सरकार ने दी है? जिन लोगों के परिवारों के लोग मरे है उन्हे कितना पैसा दिया गया और जिनके मकान जले है उनको कितना पैसा दिया गया है या दिया जायेगा? आग लगी है 11 मई को अभी तक कितना रुपया पहुचा है उस का साफ साफ उत्तर आना चाहिए ।

श्री राम निवास मिर्धा : मै निवेदन कर चुका हूं कि 8000 रुपया तात्कालिक राहत कार्य के लिए तहसीलदार ने उसी समय दे दिया था। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन के लिए मकान आदि बनाने के लिए वह और भी कुछ मदद देने वाली है।

श्री हुकम चंद कछवाय : यह 8000 रुपया पूरे गाव के लोगो को दिया जायेगा या केवल एक पीडित परिवार के लोगों को दिया जायेगा ?

श्री राम निवास मिर्धा : यह सूचना मेरे पास नही है।

SHRI BUTA SINGH (Rupar): I just want one clarification. Ordinarily, I have never intervened.

MR. SPEAKER: Ordinarily, the procedure does not allow it. Otherwise, I would have allowed you.

SHRI BUTA SINGH : I would never have intervened. It is not a question of procedure, but the question is so serious and it involves the lives of so many people. Here is the hon. Minister who has made a statement and it has been challenged by an hon. Member.

SHRI B. P. MAURYA : Yes; I am prepared to resign if whatever I have said is wrong. The FIR is wrong. The report was given to the Collector. They moved an application. All these papers are on my record. If what I say is wrong, I am prepared to resign.

श्री हुकम चन्द कछवाय : आज इतनी अधिक महंगाई के जमाने में केवल 8000 रुपया पूरे गांव का देना कहां तक ठीक होगा ? उन्हें इससे कहीं अधिक मदद चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : इस से ज्यादा जवाब वह कहां से लाये जो जानकारी उन्हें वहां से मिली था वह सब मंत्री जी ने बतला दी ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मेरा कहना है कि यहां से उनको खींचा जाय तभी वह माकूल जवाब व मदद देंगे ।

SHRI BUTA SINGH *rose*—

MR. SPEAKER : Mr. Buta Singh, yourself and Mr. Maurya can meet the Minister and tell him what are the facts. (*Interruption*)

SHRI BUTA SINGH : The hon. Minister has taken a position saying that is a question of law and order— (*Interruption*)

MR. SPEAKER : Your name is not there. How can I help?

SHRI BUTA SINGH : The facts supplied now to this House by the hon. Minister are quite different from the facts given to us.

The facts given to us are very revealing.

MR. SPEAKER : There is a procedure for it. Shri Ramkanwar. (*Interruption*)

7—7 LSS/72

श्री हुकम चन्द कछवाय : सही बात को दबाया जा रहा है । मेरी प्रार्थना है कि आप यहां से अपने इंडिपेंडेंट आदमी भेज कर इस मामले में जांच करवायें ताकि सही बात का पता लग सके ।

SHRI A. K. SEN (Calcutta—North-West) : I appeal to the hon. Minister to look into the figures. Rs. 8,000 is nothing.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA (Serampore) : He asked whether Rs. 8,000 were distributed to the whole village or to a particular man only.

MR. SPEAKER : He has replied to it. He has not got the information. (*Interruption*).

SEVERAL HON. MEMBERS *rose*—

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है यह 8000 रुपया सारे गांव को दिया है या केवल एक पीड़ित परिवार के लोगों को दिया है ?

मेरा व्यवस्था संबंधी प्रश्न है । मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे प्रश्न का पूरी तरह से उत्तर दिलवायें । मैंने पूछा है कि जो लोग मरे है उनको कितना रुपया दिया है ? और जिनके मकान जले है उन को कितना रुपया दिया है ? मंत्री महोदय ने बतलाया कि केवल 8000 रुपया दिया है । मैं जानना चाहता हूं कि जिनके परिवार के लोग मरे हैं उनको कितना दिया है या जिनके मकान जले हैं उन गांव वालों को कितना दिया है ?

श्री राम निवास मिर्धा : यह सूचना मेरे पास अभी मौजूद नहीं है । (*Interruption*)

MR. SPEAKER : I am not going to allow any more questions. Why are you interrupting Mr. Kachwai is holding up the proceedings.

श्री हुकम चन्द कछवाय : राज्य सरकार ने कितनी मदद देने की घोषणा की है और केन्द्रीय सरकार ने कितनी मदद

[श्री हुकम चन्द कछवाय]

देने की घोषणा की है इस का जवाब दिलवाइए । केन्द्रीय सरकार कितना देने वाली है वह तो कह सकते हैं । केन्द्रीय सरकार ने कितनी मदद देने की घोषणा की है ?

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । मंत्री महोदय को जो जवाब देना था वह दे चुके हैं ।

श्री रामकंवर (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बतलाया है कि राज्य सरकार से मिली सूचना यह है कि 11 मई को मछरिया गांव में ऐक्सीडेंटल फायर लग गई थी तो दरअसल यह कहा तक सही है ? यह वाकई ऐक्सीडेंटल आग थी या यह आग किसी ने लगाई थी ?

इस संबंध में मेरा निवेदन है कि जो 100 परिवार जल गये हैं उन के लिए यह जो केवल 8000 रुपया दिया गया है तो यह बहुत ही अपर्याप्त है कारण केवल 350 रुपया प्रति परिवार पड़ता है । 350 रुपया तो केवल एक खेत पर जो फूस की कच्ची झोपड़ी होती है उसी के बनाने पर 350 रुपये लग जाते हैं । आजकल के महगाई के जमाने में यह 350 रुपया बहुत ही कम दिया जा रहा है ।

इस से पता यही चलता है कि जो असली बात है उस को छिपा दिया गया है और एक बनावट व नकली तस्वीर हमारी नजर के सामने पेश की जा रही है । मेरा निवेदन है कि संसद सदस्य की एक विशेष समिति इस के लिए नियुक्त की जाय जिसमें हरिजन, आदिवासियों को एसोशिएट किया जाय और वह संसद सदस्य खुद जाकर तमाम मामले की तह में छानबीन करे ताकि सही हालात मालूम हो सके और सब को इस बात की तसल्ली हो सके कि वाकई राज्य सरकार ने जो वह दरशन अपना भेजा है वह कहा तक सही है ? क्या मंत्री महोदय इस प्रकार का कदम उठाने का कोई आश्वासन हमें दे सकेंगे ताकि हम सभी लोगों को विश्वास हो सके ?

श्री राम निवास मिर्धा : हमारी सूचना यह है कि वहा पर कच्चे फूस के मकान थे जो कि आग लगने की वजह से जल गये और जो नुकसान हुआ उस का तखमीना भी राज्य सरकार ने हमारे पास भेजा है । यह सही है कि जो 8000 रुपया मिला है वह कम है । राज्य सरकार इस बात को महसूस करती है और उसने हमें विश्वास दिलाया है कि उन को मकान बनाने के लिए और ज्यादा मदद देंगे । हम उन से निवेदन करेंगे कि जितने घर जल हैं या क्षतिग्रस्त हुए हैं, उस के हिसाब से मदद दें । साथ ही प्रधान मंत्री रिलीफ फंड से भी हम कुछ मदद देने का विचार कर रहे हैं और उस रिलीफ फंड से भी उन्हें कुछ राशन मिलेगी ।

SHRI B. S. MURTHY (Amalapuram) : Sir, on a point of order. A special responsibility has been cast on the President of India to take care of the welfare of the Scheduled Castes and Tribes. How can the hon Minister take shelter under some other provision and say that this is a law and order problem and nothing can be done by the Centre.

MR. SPEAKER . You know that this is not a point of order.

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो सूचना दी है और जो अभी वक्तव्य में यह कहा कि प्रधान मंत्री के रिलीफ फंड से भी कुछ रुपया मिलेगा । चूंकि इस पर विचार किया जा रहा है इसलिए रिलीफ फंड

से मिलने की उम्मीद है और इस के लिए तो मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं । लेकिन मैं उन से एक बात पूछना चाहता हूं कि इस देश में यह हरिजनों के साथ आये दिन घटनाएं कहीं न कहीं, किसी न किसी प्रांत मे होती रहती है । मूल प्रश्न यह है कि भले ही यह सवाल राज्य सरकारों के कानून और व्यवस्था का सवाल हो पर केन्द्र सरकार का विशेष दायित्व है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति देश में 25 सालों के बाद में न हो । मैं आप के माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन घटनाओं के मूल में दो बातें होती हैं । एक तो उनके पुश्तैनी धंधे की । जो हरिजन लोग अपने काम को छोड़कर या जो काम अब तक करते आये हैं उस को छोड़ कर दूसरा काम करना चाहते हैं तो गांव वालों का उन के ऊपर अनावश्यक दबाव होता है और उस कारण यह झगड़े होते हैं ।

दूसरा कारण यह है कि जमीन को लेकर अक्सर यह झगड़े होते हैं । क्या मंत्री महोदय इस पर गंभीरता से विचार करेंगें कि ऐसे मामलों मे जबकि हरिजन अपने ट्रेडीशनल काम को न करना चाहें तो उन पर दबाव न हो इस के लिए कानून में कोई व्यवस्था हो और ऐसा दबाव देने वाले लोगों पर कानूनी तौर पर सख्ती से काम लिया जा सके, इस का कोई विचार करेंगे ?

दूसरे खेत के मामले मे जब झगडा होता है तो उस के लिए साधारण कानून की मदद के अलावा हरिजनों के मामले में पुलिस आदि संबंधी कोई विशेष व्यवस्था करेंगे ताकि उन के खेत की रक्षा हो सके और झगड़े न हो सके इस के साथ साथ मैं इस संदर्भ में एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं ।

राज्य सरकार मकानों के बारे मे और सहायता देने का विचार कर रही है । सौभाग्य से बारिश फिर शुरू हुई है । बारिश के दिनों में यह मकान बिल्कुल नहीं बनेंगे, बारिश के बाद बनेंगे । मै जानना चाहूंगा कि इन कठिनाईयों को देखते हुए क्या मंत्री महोदय राज्य सरकार को निर्देश देंगे कि जो भी सहायता देनी हो मकानों के संबंध में उसे जितनी जल्दी से जल्दी संभव हो और जितनी ज्यादा संभव हो एक हफ्ते या पंद्रह दिन के अंदर—दें ताकि वह लोग अपने मकान बना सकें ?

श्री रामनिवास मिर्धा . यह निश्चय ही खेदजनक बात है कि स्वतंत्रता के पच्चीस वर्षों के बाद भी हमारे देश मे इस प्रकार की घटनाए होती है । केन्द्रीय सरकार ....

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore) : Is he admitting that it is not accidental? If it is acidental fire why say मुझे खेद हुआ ?आप को खेद क्यों हुआ ?

If you do not believe that it is an accidental fire, that means you are admitting that the report sent by the State Government is a bogus one.

श्री राम निवास मिर्धा : यह कहना कि राज्य सरकार ने बोगस रिपोर्ट भेजा है सही नही होगा । (**व्यवधान**) हम को यह मान कर चलना होगा कि राज्य सरकार भी इन मामलों मे उतनी ही चिन्तित है जितना यह सदन है और यह सरकार है । (**व्यवधान**) जहां तक और ज्यादा राहत देने का प्रश्न है, हम राज्य सरकार को निश्चित रूप से उन भावनाओं से अवगत करायेंगे जो इस सदन मे प्रकट की गई हैं और जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा सहायता मिल सके इस की व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : सी बी आई से इस की जांच करवाइये तब सारी बात का पता लग जायगा ।